कार्यशाला

डिजिटल युग में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व
– अभिशासन की चुनौतियों से अभिशासन में सुगमता की ओर

14-15 नवंबर 2016, नई दिल्ली

युनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सेमिनार रूम नम्बर 1

एजेंडा

पृष्ठभूमि

आईटी फॉर चेंज द्वारा सेंटर फॉर इंटरनेट ऐण्ड सोसायटी (सीआईएफ), डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन (डीईएस), मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) तथा नैशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) के साथ मिलकर 'डिजिटल युग में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व' शीर्षक पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में अधिकारों एवं सामाजिक न्याय की रूपरेखा को केंद्र में रखते हुए डेटा आधारित अभिशासन एवं डिजिटल लोकतंत्र की एक व्यापक नीतिगत समझदारी विकसित करने पर विचार किया जाएगा।

कार्यशाला के उद्देश्य :

- अभिशासन एवं निर्णय प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा के प्रयोग से लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व एवं नागरिक सहभागिता के लिए पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के आधारभूत सिद्धांतों पर विचार-विमर्श।
- अंतिम नागरिक तक के अधिकारों की रक्षा व प्रोत्साहन के लिए समर्पित एक जीवंत लोकतंत्र हेतु डिजिटल प्रौद्योगिक व डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार-विमर्श।

हम उम्मीद करते हैं कि इस दो दिवसीय चर्चा से आने वाले समय के लिए एक सामूहिक कार्रवाई की ठोस रूपरेखा और रणनीति सामने आएगी।

एजेंडा

14 नवंबर	**पहला दिन**
09.00 – 09.30 बजे	**पंजीकरण**
09.30 – 10.30 बजे	**भूमिका** (क) स्वागत एवं परिचय
10.30 – 10.50 बजे	चाय
10.50 – 12.20 बजे	**सत्र 1 – डिजिटल भारत में लोकतंत्र : क्या दांव पर लगा है?** पिछले एक दशक के दौरान ई-गवर्नेंस की परिघटना के उदय के साथ हमें बहुत सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं; अधिकारों की डिलीवरी में जनधन-आधार-मोबाइल का बढ़ता प्रयोग, साझा सेवा केंद्रों के जरिए सेवाओं का निजीकरण, शिकायतों की निगरानी और अद्यतन के लिए एमआईएस आधारित व्यवस्था, और हाल ही में निर्णय प्रक्रिया के लिए बिग डेटा (एलगोरिदम नामक गणितीय सूत्रों के के आधार पर नागरिकों के डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण) के इस्तेमाल का लगातार बढ़ता चलन। यह पैनल इस पर विचार करेगा कि इस बदलाव से नागरिकों के जीवन पर तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के लिए क्या निहितार्थ निकलते हैं और आने वाले वक्त में हम क्या कदम उठा सकते हैं **वक्ता** निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन ऊषा रामानाथन, विधि विशेषज्ञ सुमन्द्रो चट्टोपाध्याय, सेंटर फॉर इंटरनेट ऐण्ड सोसायटी **संचालन** परमिंदर जीत सिंह, आईटी फॉर चेंज
12.20 – 1.10 बजे	**सत्र 2 – नई अभिशासन संरचना में क्या नया है? जमीनी लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है?** इस लेक्चर में अभिशासन के क्षेत्र में की जा रही उन नई व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जिनके माध्यम से निजी ताकतें लोकतंत्र को निर्धारित करने वाले मुख्य बिंदुओं पर हावी होती जा रही हैं। इस सत्र में 'एलगॉरिदम आधारित निर्णय प्रक्रिया', 'बिग डेटा एनालिसिस' वगैरह की अवधारणाओं पर भी चर्चा की जाएगी। **वक्ता** प्रबीर पुरकायस्थ, सोसायटी फॉर नॉलेज कॉमन्स **सत्र की अध्यक्षता** निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन
1.10 – 2.10 बजे	लंच
2.10 – 3.45 बजे	**सत्र 3 – तकनीकशाही के दौर में नागरिक सक्रियता की भूमिका**

	इस सत्र में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि सूचनाओं तक पहुंच, शिकायतों की सुनवाई और परामर्श प्रक्रियाओं में नागरिकों के अनुभव अभिशासन में नई तकनीक के आने से किस तरह बदलते जा रहे हैं। क्या नागरिकों को कोई नकारात्मक अनुभव मिल रहे हैं? नागरिक सहभागी स्थानीय अभिशासन के लिए डेटा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? **वक्ता** शंकर, मजदूर किसान शक्ति संगठन राजेन्द्रन नारायणन, प्रोग्राम फॉर लिबरेशन टैक्नोलॉजी अंबर सिन्हा, सेंटर फॉर इंटरनेट ऐण्ड सोसायटी दीप्ति भारतर, आईटी फॉर चेंज **अध्यक्षता** सेजल डांड, आनंदी एवं मकाम **चर्चा का संचालन** करुणा मुथैया, पुधू वाज़वू प्रॉजेक्ट, तमिलनाडु सरकार विपुल मुद्गल, इनक्लुसिव मीडिया फॉर चेंज
3.45 – 4.15 बजे	चाय
4.15 – 5.15 बजे	**सत्र 4 – स्मार्ट सिटी का अभिशासन** **प्रारूप : पैनल प्रस्तुतियां और उनके बाद खुली चर्चा** स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 से अधिक शहरों में पीपीपी मॉडल के आधार पर आईटी प्रौद्योगिक आधारित शहरों के निर्माण की परियोजना शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के तहत निजी कंपनियां इंटरनेट से जुड़े कैमरों, मोबाइल फोनों और अन्य उपकरणों पर उपलब्ध डिजिटल सूचनाओं को इकट्ठा करके विभिन्न सेवाओं के संचालन के लिए आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित करेंगी। इस सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी कि स्मार्ट सिटीज की इस अवधारणा पर हमें पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों हैं ताकि निजी मुनाफे के लिए हाशियाई लोगों और उनके डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके। **वक्ता** क्षितिज उर्स, ऐक्शन एड स्वपना सुंदर, आईपी डोम **अध्यक्षता** अनुपम सराफ, शोधकर्ता **चर्चा का संचालन** सुकर्ण सिंह, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर जीविका शिव, आनंदी अनंत शर्मा, ऐक्सेस नाऊ

…0 - 7.30 बजे	आगे की कार्यदिशा पर चर्चा के लिए आयोजकों की मीटिंग
15 नवंबर	**दूसरा दिन**
9.30 - 11.00 बजे	**सत्र 5 : वापस जड़ों की ओर - डिजिटल अभिशासन के युग में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के प्रारंभिक सिद्धांत** आज नागरिकों को लोक सूचनाओं व लाभों तक पहुंच तथा सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए पुराने कायदे-कानून ही काफी नहीं हैं। लिहाजा, इस सत्र में ऐसी नयी वैधानिक-संस्थागत सुरक्षाओं, प्रशासकीय प्रक्रियाओं, तकनीकी-डिजाइन संबंधी सिद्धांतों और डेटा अभिशासन दिशानिर्देशों पर विचार किया जाएगा जो डिजिटल युग में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का आधार बन सकते हैं। **वक्ता** अनुपम सराफ, शोधकर्ता (कॉम्पलेक्स सिस्टम्स) राहुल शर्मा, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ओसामा मंज़र, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन **अध्यक्षता** अंजलि भारद्वाज, नैशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन **चर्चा का संचालन** ज्याँ द्रेज़, रांची विश्वविद्यालय कर्नल मैथ्यू थॉमस, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एवं सेवानिवृत सेना अधिकारी इनायत साभिखी, पीपुल्स ऐक्शन फॉर एम्प्लायमेंट गारंटी, पेंशन परिषद
11.00 - 11.20 बजे	चाय
11.20 - 11.30 बजे	**समूह कार्य के लिए निर्देश - प्रत्येक समूह के लिए पृष्ठभूमि नोट्स का वितरण**
11.30 - 01.00 बजे	**समूह कार्य : डिजिटल युग में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का नक्शा** यह सत्र इन चार शीर्षकों पर बनाए गए समूहों में चलाया जाएगा : **कल्याणकारी सेवाओं में उत्तरदायित्व; डेटा अभिशासन रूपरेखा; सहभागिता का अधिकार तथा नई अभिशासन व्यवस्था में निजी शक्तियों का नियमन।**
1.00 - 2.00 बजे	**लंच**
2.00 - 3.15 बजे	**चाय के साथ समूह कार्य जारी रहेगा।**
3.15 - 4.30 बजे	**समापन सत्र : धन्यवाद ज्ञापन तथा खुली चर्चा।**